

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 215] No. 215] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 8, 2015/चैत्र 18, 1937

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 8, 2015/CHAITRA 18, 1937

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2015

सं. 25/2015-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 270(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.08 के साथ पठित पैरा 3.10 के अंतर्गत क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा जारी भारतीय योजना के तहत सेवाओं का निर्यात शुल्क जमा पर्ची (यहां इसके बाद उक्त पर्ची कही जाएगी) के एवज में जब वस्तुएं भारत में आयात की जाती है तो उनको निम्नलिखित से छूट प्रदान करती है,-

- (क) संपूर्ण सीमा शुल्क जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (यहां इसके बाद उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम कहा जायेगा) की पहली अनुसूची के अंतर्गत उनपर लगाया जाने योग्य होता है; और
- (ख) संपूर्ण अतिरिक्त शुल्क जो कि उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत उनपर लगाया जाने योग्य होता है;
- 2. यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, नामश:-

1606 GI/2015

- (1) यह कि भारत में स्थित एक सेवा प्रदाता को विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के परिशिष्टों तथा आयात निर्यात प्रपत्रों के परिशिष्ट 3घ में सूचीबद्ध अधिसूचित सेवाओं का निर्यात करने पर उक्त पर्ची में शुल्क जमा किया जाता है;
- (2) यह कि आयात और निर्यात उन समुद्री बंदरगाहों, विमानपत्तनों अथवा इनलैंड कंटेनर डिपों के माध्यम से अथवा उन भू-सीमाशुल्क स्टेशनों के जिरए से जिनका उल्लेख दिनांक 1 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना संख्या 16/2015-सीमा -शुल्क की सारणी 2 में किया गया है अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 4 के अतर्गत अधिसूचित विशेष आर्थिक जोन के माध्यम से किए जाते हैं:

बशर्ते कि सीमा शुल्क आयुक्त अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विशेष आदेश द्वारा अथवा सार्वजनिक नोटिस द्वारा और उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन किसी अन्य समुद्री बंदरगाह, विमानपत्तन, इनलैंड कंटेनर डिपो अथवा भू सीमा शुल्क स्टेशन के माध्यम से आयात और निर्यात की अनुमति प्रदान कर सकते हैं;

- (3) यह कि उक्त पर्ची, उक्त पर्ची पर उल्लखित पंजीकरण पत्तन पर सीमाशुल्क प्राधिकारी के यहां पंजीकृत है;
- (4) यह कि उक्त पर्ची माल पर लगने वाली ड्यूटी के डेबिट हेतु निकासी के समय उपयुक्त सीमाशुल्क अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी तथा उपयुक्त सीमाशुल्क अधिकारी इस छूट के अंतर्गत पहले ही डेबिट की गई राशि तथा अधिसूचना सं 21/2015-केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिनांक 08.04.2015 तथा अधिसूचना सं 11/2015 सेवा कर दिनांक 08.04.2015 के तहत डेबिट की गई राशि को ध्यान में रखते हुए इस छूट के बिना, माल पर लगने वाली ड्यूटी डेबिट करेगा;
- (5) यह कि उक्त पर्ची और वस्तुएं जो इसके बदले आयात की गई हैं वह मुक्त रूप से हस्तांतरणीय होंगी:
- (6) जहां आयातकर्ता उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत लगने वाले अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट का दावा नहीं करता है तो उसे संबंधित सीमाशुल्क की अतिरिक्त ड्यूटी की संगणना हेतु उक्त शुल्क से छूट का लाभ नहीं लेने वाला माना जाएगा;
- (7) यह कि आयातकर्ता को उक्त पर्ची में से डेबिट की गई राशि के एवज में उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के तहत उस पर लगने वाली सीमा शुल्क के प्रतिअदायगी की हकदारी होगी;
- (8) यह कि आयातकर्ता को उक्त पर्ची में से डेबिट की गई राशि के एवज में उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत लगने वाली अतिरिक्त ड्यूटी के प्रतिअदायगी अथवा सेनवेट क्रेडिट की हकदारी होगी;

(9) यह कि इस अधिसूचना के अंतर्गत उन मदों को लाभ उपलब्ध नहीं होगा जिन्हें विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के परिशिष्टों और आयात निर्यात प्रपत्रों के परिशिष्ट 3क में सूचीबद्ध किया गया है।

स्पष्टीकरण. - इस अधिसूचना में -

- (I) "पूंजीगत वस्तुओं" का वही अर्थ है जो कि विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.08 में दिया गया है।
- (II) "विदेश व्यापार नीति" से अभिप्राय विदेश व्यापर नीति, 2015-2020 से है जिसका प्रकाशन भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या 01/2015-2020, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 समय-समय पर यथा संशोधित, के द्वारा किया है;
- (III) "वस्तुओं" का अर्थ ऐसे किसी निविष्टियां या वस्तुओं से है जिसमें पूंजीगत माल भी शामिल है।
- (IV) "क्षेत्रीय प्राधिकारी" से अभिप्राय उस विदेश व्यापार महानिदेशक से है जिसकी नियुक्ति विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 6 के अंतर्गत की गई है या ऐसे अधिकारी से है जिसे उसके द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकार प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो;

[फा. सं. 605/55/2014-डी बी के] संजय कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2015

No. 25/2015-Central Excise

- **G.S.R. 270(E).** In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods when imported into India against a Service Exports from India Scheme duty credit scrip issued by the Regional Authority under paragraph 3.10 read with paragraph 3.08 of the Foreign Trade Policy (hereinafter referred to as the said scrip) from,-
 - (a) the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as said Customs Tariff Act); and
 - (b) the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act.
- 2. The exemption shall be subject to following conditions, namely:-
 - (1) that the duty credit in the said scrip is issued to a service provider located in India against export of notified services listed in Appendix 3D of Appendices and Aayat Niryat Forms of Foreign Trade Policy 2015-2020;
 - (2) that the imports and exports are undertaken through the seaports, airports or through the inland container depots or through the land customs stations as mentioned in the Table 2 annexed to the Notification No. 16/2015- Customs dated 01.04.2015 or a Special Economic Zone notified under section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005):

Provided that the Commissioner of Customs may within the jurisdiction, by special order, or by a Public Notice, and subject to such conditions as may be specified by him, permit import and export through any other sea-port, airport, inland container depot or through any land customs station;

- (3) that the said scrip is registered with the Customs Authority at the port of registration specified on the said scrip;
- that the said scrip is produced before the proper officer of customs at the time of clearance for debit of the duties leviable on the goods and the proper officer of customs, taking into account the debits already made under this exemption and debits made under the notification Nos. 21 of 2015 Central Excise, dated the 8th April, 2015 and 11 of 2015 Service Tax, dated the 8th April, 2015, shall debit the duties leviable on the goods, but for this exemption;
- (5) that the said scrip and goods imported against it shall be freely transferable;
- (6) that where the importer does not claim exemption from the additional duty of customs leviable under section 3 of the said Customs Tariff Act, he shall be deemed not to have availed the exemption from the said duty for the purpose of calculation of the said additional duty of customs;
- (7) that the importer shall be entitled to avail drawback of the duty of customs leviable under the First Schedule to the said Customs Tariff Act against the amount debited in the said scrip;
- (8) that the importer shall be entitled to avail drawback or CENVAT credit of additional duty leviable under section 3 of the said Customs Tariff Act against the amount debited in the said scrip.
- (9) that the benefit under this notification shall not be available to the items listed in Appendix 3A of Appendices and Aayat Niryat Forms of Foreign Trade Policy 2015-2020.

Explanation.- In this notification-

- (I) "Capital goods" has the same meaning as assigned to it in paragraph 9.08 of the Foreign Trade Policy;
- (II) "Foreign Trade Policy" means the Foreign Trade Policy, 2015-2020, published by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry notification number 01/2015-2020, dated the 1st April 2015 as amended from time to time;
- (III) "Goods" means any inputs or goods including capital goods;
- (IV) "Regional Authority" means the Director General of Foreign Trade appointed under section 6 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992) or an officer authorised by him to grant an authorisation including a duty credit scrip under the said Act.

[F. No. 605/55/2014-DBK]

SANJAY KUMAR, Under Secy.